

LOW COST VNO LICENCE FOR BROADBAND DELIVERY

The VNO (Virtual Network Operator) licence for broadband delivery is the equivalent of an LCO licence for Cable TV.

In our February 2017 article, we have detailed the procedure and cost for obtaining an Internet Service Provider's (ISP) licence.

The ISP licence is compulsory to set up a business that receives bulk internet and subsequently distributes it to multiple retail customers. An ISP licence is expensive to obtain. It requires an entry fee of ₹ 30 lakhs for a national licence or ₹ 2 lakhs for a category B (Metros or telecom circle) or ₹ 20,000 for category C (all areas not covered by category B) licence.

In addition, the ISP must provide a performance bank guarantee ranging from ₹ 2 crores to ₹ 50,000 plus financial bank guarantee. (₹ 10 lakhs to ₹ 10,000) plus an application fee (₹ 50,000 to ₹ 10,000).

Of course, the most important a significant expense is the recurring payment of Adjusted Gross Revenue (AGR) of 8% to be paid to the Government. This typically amounts to 8% of all collections of the ISP.

It Is Illegal To Deliver Broadband Without An ISP or VNO License

ACTION AGAINST UNLICENSED BROADBAND

The government wants to ensure it collects the 8% monthly AGR on broadband services and has started actively prosecuting any broadband service provider who does not have an operating license. It is therefore absolutely essential that all broadband service providers immediately obtain either an ISP license or a VNO license.

ब्रॉडबैंड डिलिवरी के लिए कम लागत वाली वीएनओ लाइसेंस

ब्रॉडबैंड डिलिवरी के लिए वीएनओ (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर) लाइसेंस केवल टीवी के लिए एक एलसीओ लाइसेंस के बराबर है।

हमारे फरवरी 2017 के लेख में हमने इंटरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) के लाइसेंस पाने के लिए प्रक्रिया और लागत का विवरण प्रदान किया था।

एक ऐसे कारोबर की स्थापना के लिए आईएसपी लाइसेंस अनिवार्य है जो कि थोक इंटरनेट प्राप्त करता है और उसके बाद इसे वह अपने विभिन्न खुदरा उपभोक्ताओं को वितरित करता है। आईएसपी लाइसेंस प्राप्त करना काफी महंगा है। इसके लिए राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए 30 लाख रुपये, बी श्रेणी (मेट्रो या टेलीकॉम सर्किल) के लिए 2 लाख रुपये या सी श्रेणी (श्रेणी बी द्वारा कवर नहीं किये गये सभी क्षेत्र) के लाइसेंस के लिए 20,000 रुपये के प्रवेश शुल्क की जरूरत होती है।

इसके अलावा आईएसपी को 2 करोड़ रुपये से 50,000 रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी के साथ वित्तीय बैंक गारंटी (10 लाख रुपये से 10,000 रु) और आवेदन शुल्क (50,000 रुपये से 10,000 रुपये) प्रदान करने की जरूरत है।

वैशक सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय व्यय है सरकार को 8% समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का भुगतान करना है। यह आमतौर पर आईएसपी के सभी संग्रहों का 8% है।

बिना आईएसपी या वीएनओ लाइसेंस के ब्रॉडबैंड डिलिवर करना गैर-कानूनी है

बिना लाइसेंस वाले ब्रॉडबैंड के खिलाफ कार्रवाई

सरकार चाहती है कि ब्रॉडबैंड सेवाओं पर 8% मासिक एजीआर के संग्रह को सुनिश्चित करे और इस क्रम में उसने किसी भी ऐसे ब्रॉडबैंड सेवा प्रदायक को गिरफ्तार करने की शुरुआत की है जिसके पास संचालन लाइसेंस नहीं है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि सभी ब्रॉडबैंड सेवा प्रदायक तत्काल आईएसपी लाइसेंस या वीएनओ लाइसेंस में से कोई प्राप्त करें।

VNO LICENCE

LOW COST LICENSE

Providing widespread broadband connectivity throughout the country has been declared as a priority by the Indian Government.

The Government realised that the large Performance Bank Guarantee required for an ISP licence inhibits small companies from entering the business and thereby inhibiting broadband connectivity in smaller markets countrywide.

VNO LICENCE

On June 3, 2016, DoT opened a new low cost license called Unified Licence VNO (UL-VNO).

It is hoped that the VNO (Virtual Network Operator) license regime will help spread the internet better in areas where large firms are typically not interested in, such as smaller towns.

However, the VNO license can be used for broadband delivery anywhere in India, including metro cities.

*The Broadband VNO
Is Similar To A Cable TV LCO*

VNO & ISP

The ISP for broadband is similar to a Cable TV MSO or Headend.

The VNO (Virtual Network Operator) from broadband plays the same role as an LCO for Cable TV.

The VNO license permits the VNO to distribute broadband without having his own core infrastructure. The VNO uses the core infrastructure of the ISP.

The VNO must pay a license fee of 8% of his Adjusted Gross Revenue.

LICENCE TERMS

- Depending on the VNO license type applied for, a licensed VNO can deliver any type of telecom services - including home telephony, broadband and OTT services like messaging, Voice over Internet Protocol (VoIP).
- The License will be issued / rejected within 60 days, and is valid for 10 years.
- Applicant must be an Indian company.
- Each company can apply for only 1 VNO license.

कम लागत वाला लाइसेंस

भारत सरकार ने देशभर में विस्तृत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने को प्राथमिकता के रूप में घोषित किया है।

सरकार ने महसूस किया है कि आईएसपी लाइसेंस के लिए आवश्यक परफॉरमेंस बैंक गारंटी की बड़ी मात्रा के चलते छोटी कंपनियां इस व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं और जिससे देशभर में छोटे बाजारों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बाधित हो रही है।

वीएनओ लाइसेंस

3 जून 2016 से डॉट ने यूनिफाइड लाइसेंस वीएनओ (यूएल-वीएनओ) नामक नये निम्न लागत वाले लाइसेंस जारी करना शुरू किया।

यह उम्मीद की गयी कि वीएनओ (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर) लाइसेंस युग उन क्षेत्रों में अच्छी तरीके से इंटरनेट का प्रचार करेगा जहां कि बड़ी कंपनियां आमतौर पर रुचि नहीं दिखाती हैं, जैसे छोटे शहर।

हालांकि वीएनओ लाइसेंस का इस्तेमाल मेट्रो शहरों सहित भारत में कहीं भी ब्रॉडबैंड डिलिवरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

*ब्रॉडबैंड वीएनओ एक केवल टीवी
एलसीओ की भांति है*

वीएनओ व आईएसपी

ब्रॉडबैंड के लिए आईएसपी एक केवल टीवी एमएसओ या हेडएंड की भांति है।

ब्रॉडबैंड से वीएनओ (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर) वही भूमिका निभाता है जो कि केवल टीवी के लिए एलसीओ निभाता है।

वीएनओ लाइसेंस अनुमति देता है कि वीएनओ बिना अपने आधारभूत संरचना के ब्रॉडबैंड को वितरित करे। वीएनओ, आईएसपी के मुख्य बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करता है।

वीएनओ को भी अपने समायोजित सकल राजस्व के 8% लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

लाइसेंस शर्तें

- आवेदन किये गये लाइसेंस के प्रकार के आधार पर लाइसेंस प्राप्त वीएनओ किसी तरह के टेलीकॉम सेवाओं को डिलिवर कर सकता है—जिसमें घरेलू टेलीफोनी, ब्रॉडबैंड और वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP), मेसेजिंग जैसी ओटीटी सेवाएं शामिल हैं।
- लाइसेंस को 60 दिनों के भीतर जारी/अस्वीकृत किया जायेगा और यह 10 वर्षों के लिए वैध रहेगी।
- आवेदक निश्चित तौर पर भारतीय कंपनी होगी।
- हर कंपनी सिर्फ एक वीएनओ लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है।

VNO LICENCE

- Each VNO can partner with a single ISP.
- No beneficial interests allowed between a VNO and ISP.
- VNOs can create their own delivery platform for customer service, billing and VAS.
- CAF verification & number activation shall be the VNO's responsibility.
- Multiple VNO licences can be issued to different companies servicing the same area.

The above points show the close similarity between a VNO license for broadband and an LCO license for Cable TV.

LICENSE APPLICATION

The ISP and VNO license application format is available on the DoT website:

www.dot.gov.in

Completed license application forms, or queries or communication can also be sent to:

Government Of India

Ministry Of Communications & IT
Department Of Telecommunications
Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road,
New Delhi-110 001.

VNO VS ISP

Table-1 summarises the financial liabilities for both ISPs and VNOs.

The (one time) Entry Fee for the VNO license is 50% that paid for the ISP license.

The Application Fee is unchanged.

Bank guarantees are a major expense especially for small players. Banks will almost always demand deposit of an amount equal to the full bank guarantee. This locks up huge resources for any small company.

*No Performance Bank Guarantee
Required From A VNO*

PERFORMANCE BANK GUARANTEE

The ISP has a roll out obligation as part of the ISP license. Hence the ISP is required to submit a very substantial Performance Bank Guarantee.

In contrast, the VNO does not have a roll out obligation, and hence is exempt from providing a Performance BG.

- हर वीएनओ एक आईएसपी के साथ सहयोगी बन सकता है।
- वीएनओ और आईएसपी के बीच कोई लाभकारी हित की अनुमति नहीं होगी।
- वीएनओ उपभोक्ता सेवा, बिलिंग और वीएस के लिए अपने खुद का डिलिवरी प्लेटफॉर्म बना सकता है।
- सीएएफ वेरिफिकेशन और नंबर एक्टिवेशन की जिम्मेवारी वीएनओ की होगी।
- एक ही क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों को अनेक वीएनओ लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

उपरोक्त बातें केवल टीवी के लिए एक एलसीओ लाइसेंस और ब्रॉडबैंड के लिए वीएनओ लाइसेंस के बीच निकट समानता दिखाती हैं।

लाइसेंस आवेदन

आईएसपी और वीएनओ लाइसेंस आवेदन फॉरमेट, डॉट के वेबसाइट www.dot.gov.in पर उपलब्ध है:

पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन, या किसी तरह के प्रश्न या सूचना को निम्न पते पर भेजा जा सकता है:

भारत सरकार

संचार व आईटी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20, अशोका रोड,

नयी दिल्ली-110 001

वीएनओ बनाम आईएसपी

टेबल-1 में आईएसपी व वीएनओ के लिए वित्तीय देयताओं का सारांश है। वीएनओ लाइसेंस के लिए एंट्री शुल्क (एक बार) आईएसपी लाइसेंस के लिए भुगतान किये जाने वाले शुल्क के 50% है।

आवेदन शुल्क में कोई बदलाव नहीं है।

छोटी कंपनियों के लिए बैंक गारंटी सबसे प्रमुख व्यय है। बैंक लगभग हमेशा पूर्ण गारंटी के बराबर राशि जमा करने की मांग करेंगे। यह किसी भी छोटी कंपनी के लिए भारी संसाधनों को लॉक करता है।

*एक वीएनओ से किसी तरह के बैंक गारंटी
की जरूरत नहीं होती*

परफॉरमेंस बैंक गारंटी

आईएसपी का आईएसपी लाइसेंस के हिस्से के रूप में संरचना लगाने का दायित्व होता है। इसलिए आईएसपी को बहुत महत्वपूर्ण परफॉरमेंस बैंक गारंटी जमा करने की जरूरत होती है। इसके मुकाबले वीएनओ के पास किसी तरह के संरचना लगाने का दायित्व नहीं होता और इसलिए उसे परफॉरमेंस बीजी प्रदान करने से छूट दी गयी है।

VNO LICENCE

	ENTRY FEE	APPLICATION FEE	PERFORMANCE BANK GUARANTEE	FINANCIAL BANK GUARANTEE	MONTHLY AGR
ISP Category A VNO Category A	₹ 30 Lakhs ₹ 15 Lakhs	₹ 50,000 ₹ 50,000	₹ 2 Crores NIL	₹ 10 Lakhs ₹ 5 Lakhs	8% 8%
ISP Category B VNO Category B	₹ 2 Lakhs ₹ 1 Lakhs	₹ 15,000 ₹ 15,000	₹ 10 Lakhs NIL	₹ 1 Lakh ₹ 50,000	8% 8%
ISP Category C VNO Category C	₹ 20,000 ₹ 10,000	₹ 10,000 ₹ 10,000	₹ 50,000 NIL	₹ 10,000 ₹ 5,000	8% 8%

Table-1: Costs of ISP and VNO licenses.

	प्रवेश शुल्क	आवेदन शुल्क	परफॉरमेंस बैंक गारंटी	फाइनेंशियल बैंक गारंटी	मासिक एजीआर
आईएसपी श्रेणी ए वीएनओ श्रेणी ए	30 लाख रु 15 लाख रु	50,000 रु 50,000 रु	2 करोड़ रु शून्य	10 लाख रु 5 लाख रु	8% 8%
आईएसपी श्रेणी बी वीएनओ श्रेणी बी	2 लाख रु 1 लाख रु	15,000 रु 15,000 रु	10 लाख रु शून्य	1 लाख रु 50,000 रु	8% 8%
आईएसपी श्रेणी सी वीएनओ श्रेणी सी	20,000 रु 10,000 रु	10,000 रु 10,000 रु	50,000 रु शून्य	10,000 रु 5,000 रु	8% 8%

टेबल-1 आईएसपी व वीएनओ लाइसेंस की लागत

FINANCIAL BANK GUARANTEE (FBG)

The amount of FBG shall be equivalent to the estimated sum payable equivalent to License fee for 2 quarters and other dues not otherwise securitized.

The amount of FBG is reviewed every 6 months by DoT.

Initially, the FBG must be valid for 1 year and must be independently renewed annually by the licensee, at least one month prior to date of its expiry.

Typically, the financial bank guarantees to be submitted by a VNO are 50% of those required from ISPs.

ISPs & VNOs Must Pay 8% AGR

AGR

The largest outflow for the license holder is however, the recurring Adjusted Gross Revenue (AGR) payable to the government. It is the same @ 8% for both, ISPs and VNOs.

GROSS REVENUE

According to the DoT, "The Gross Revenue shall be inclusive of all types of revenue from Internet services, revenue from Internet access service,

फाइनेंशियल बैंक गारंटी (एफबीजी)

एफबीजी की रकम 2 क्वार्टर के लिए लाइसेंस शुल्क के बराबर देय अनुमानित राशि के बराबर होगी और अन्य बकाया अन्यथा प्रतिभूतिकृत नहीं होगी। एफबीजी की रकम की समीक्षा डॉट द्वारा हर 6 महीने में की जायेगी।

आरंभ में एफबीजी 1 साल के लिए वैध होगी और लाइसेंस धारक द्वारा इसके समाप्त होने की तारीख से कम से कम एक महीने पहले स्वतंत्र रूप से इसका वार्षिक नवीकरण करना चाहिए।

आमतौर पर वीएनओ द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बैंक गारंटी, आईएसपी से जिसकी जरूरत होती है उसके मुकाबले 50% होती है।

आईएसपी व वीएनओ 8% एजीआर का भुगतान करेंगे

एजीआर

हालांकि लाइसेंस धारक के लिए सबसे बड़ा आउटफ्लो सरकार को भुगतान किया जाने वाल आवर्ती समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) होता है। यह आईएसपी और वीएनओ दोनों के लिए समान 8% होता है।

सकल राजस्व

डॉट के मुताबिक 'सकल राजस्व में इंटरनेट सेवाओं से सभी तरह का राजस्व, इंटरनेट एक्सेस सेवा से राजस्व, इंटरनेट सामग्री से

VNO LICENCE

revenue from internet contents, revenue from Internet Telephony service, revenue from activation charges, revenue from sale, lease or renting of bandwidth, links, R&G cases, Turnkey projects, revenue from IPTV service, late fees, sale proceeds of terminal equipments, revenue on account of interest, dividend, value added services, supplementary services, revenue from permissible sharing of infrastructure, etc. allowing only those deductions available for pass through charges and taxes/levies as in the case of access services, without any set-off for related item of expense, etc."

ADJUSTED GROSS REVENUE

According to the DoT, "for the purpose of arriving at the "Adjusted Gross Revenue (AGR)" the following shall be excluded from the Gross Revenue to arrive at the AGR:

- (i) Charges actually paid to the NSOs. Charges paid to NSO(s) shall be limited to applicable access charges such as carriage charges, termination charges and roaming charges.
- (ii) Service Tax on provision of service and Sales Tax actually paid to the Government if gross revenue had included the component of Sales Tax and Service Tax."

NOTE: A UL (VNO) Licensee with authorization for Internet Service shall be parent to NSO (Network Service Operator) only. Any Interconnection with Access Service provider, ISPs, ILDs, VSATs, NLDs shall be through the NSO to which it is parented.

SUMMARY

The VNO license provides broadband service providers the equivalent of an LCO license for Cable TV.

The VNO license is ideal for small broadband networks who intend to only distribute / retail broadband to their consumers, without setting up an entire ISP (headend) infrastructure.

The government is cracking down on all broadband retailers who are operating without a ISP or VNO license, and therefore not paying the 8% AGR due to the government.

As a result, all broadband operators are urged to obtain their license to commence broadband operations, which provide much higher returns than Cable TV retailing. ■

राजस्व, इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं से राजस्व, एक्टिवेशन शुल्क से राजस्व, बैंडविड्थ, लिंक, आरएंडजी मामले, टर्नकी योजनाओं की विक्री, लीज या किराये से राजस्व, आईपीटीवी सेवा, देर से शुल्क, टर्मिनल उपकरण की विक्री से प्राप्त राजस्व, ब्याज, लाभांश, मूल्य आधारित सेवाओं, पूरक सेवाओं से प्राप्त राजस्व, बुनियादी सेवाओं को साझा करने से प्राप्त राजस्व आदि शामिल है, जो कि एक्सेस सेवाओं के मामले में, व्यय के संबंधित मदों के लिए कोई सेट-ऑफ किये बिना शुल्क और करों/लेवी के माध्यम से पास के लिए उपलब्ध उन कटौती की अनुमति देना आदि' है।

समायोजित सकल राजस्व

डॉट के मुताबिक 'समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)' पर पहुंचने के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित को एजीआर पर पहुंचने के लिए सकल राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है:

- (i) एनएसओ को भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क। एनएसओ को दिये गये शुल्क कैरिज शुल्क, टर्मिनेशन शुल्क और रोमिंग शुल्क जैसे पहुंच शुल्क तक सीमित होगा।
- (i) सेवाओं के प्रावधान पर सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स का भुगतान वास्तव में सरकार को किया जाना चाहिए, यदि समग्र राजस्व में विक्री कर और सर्विस टैक्स के घटक शामिल हो तो।'

नोट: इंटरनेट सेवाओं के लिए अर्थोराइजेशन के साथ एक यूएल (वीएनओ) लाइसेंस धारक केवल एनएसओ (नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर) के लिए अभिभावक होंगे। एक्सेस सेवा प्रदायक, आईएसपी, आईएलडी, वीसैट, एनएलडी के साथ किसी तरह का इंटरकनेक्शन एनएसओ की सहायता से होगी जिसके लिए वे अभिभावक होंगे।

निष्कर्ष

वीएनओ लाइसेंस प्रदायक द्वारा प्रदान किये जाने वाले ब्रॉडबैंड सेवा केवल टीवी के लिए एलसीओ लाइसेंस के बराबर होती है।

वीएनओ लाइसेंस उन छोटे नेटवर्कों के लिए आदर्श है जो पूरी आईएसपी (हेडएंड) संरचना को स्थापित किये बिना अपने उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड की खुदरा/वितरित करने की इच्छा रखते हैं।

सरकार उन सभी ब्रॉडबैंड विक्रेताओं पर कार्रवाई कर रही है जो कि आईएसपी या वीएनओ लाइसेंस के बिना संचालन कर रहे हैं और इस तरह सरकार को दिये जाने वाले 8% एजीआर का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

परिणामस्वरूप सभी ब्रॉडबैंड संचालकों से आग्रह है कि वे ब्रॉडबैंड संचालन शुरू करने से पहले अपने लाइसेंस प्राप्त करें, जो कि केवल टीवी के मुकाबले अपेक्षाकृत अच्छा रिटर्न प्रदान करता है। ■